



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 487]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 1995/अग्रहायण 6, 1917

No. 487]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 1995/AGRAHAYANA 6, 1917

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 762(अ):— केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है,

(ख) “केन्द्रीय प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(ग) “सदस्य” से, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है,

(घ) “सदस्य सचिव” से, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त सदस्य सचिव अभिप्रेत है,

(ङ) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है किन्तु वे परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

3 केन्द्रीय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या अनुभव और अर्हताएँ :—

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण में बारह से अधिक सदस्य होंगे।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :—

- (i) भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के, विधि कार्य विभाग के सचिव या उसका कोई नाम निर्देशित ;
- (ii) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, के व्यय विभाग में सचिव या उसका कोई नाम निर्देशित, और
- (iii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के दो अध्यक्ष जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु, केन्द्रीय प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक, इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण का गठन होने तक, ऐसे गठन से पूर्व विद्यमान किन्हीं दो राज्य विधिक सेवा और सलाह बोर्डों या समिति चाहे वे किसी, नाम से ज्ञात हो, के अध्यक्षों को, नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अन्य सदस्यों को, उनमें से नामनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके पास इस नियम के उपनियम (4) में विहित अनुभव और अर्हताएं हैं ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह :—

- (क) विधि के क्षेत्र में कोई प्रख्यात व्यक्ति न हो, या
- (ख) ऐसा कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो विधिक सेवा स्कीमों को कार्यान्वित करवाने में विशेष रूप से रुचि न रखता हो, या
- (ग) ऐसा कोई विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जो कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्रियों बालक, ग्रामीण और शहरी श्रमिक भी हैं, के उत्थान में न लगा हो ।

4. सदस्य सचिव की नियुक्ति :— केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास नियम 5 में यथाविहित अनुभव और अर्हताएं हैं, केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त कर सकेगी ।

5. केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य सचिव के लिए अनुभव और अर्हताएं और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य :—

कोई व्यक्ति सदस्य सचिव नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह :—

(क) भारतीय विधिक सेवा का ऐसा कोई अधिकारी, जिसने भारत सरकार के अथवा सचिव के नीचे की पंक्ति का पद धारण न किया हो, या

(ख) राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा कोई सदस्य जिसने जिला न्यायाधीश का पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण न किया हो; या

(ग) केन्द्रीय सेवा की अन्य संगठित सेवाओं का कोई ऐसा अधिकारी जिसने भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य पद, कप से कम तीन वर्ष तक धारण न किया हो; या

(घ) संगठित राज्य सेवा का ऐसा कोई अधिकारी, जिसने भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य पद को कम से कम पांच वर्ष तक धारण न किया हो ।

ऐसे व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी जो प्रशासनिक वितीय और विधिक सहायता में अनुभव रखते हों ।

6. सदस्य सचिव की शक्तियों और कृत्य :—

अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य सचिव की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :—

(क) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा स्कीम की रीति और कार्यक्रमों को कार्यरूप देना और संपूर्ण देश में उनके प्रभावी मानीटरिंग और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ख) केन्द्रीय सरकार के विभागाध्यक्ष की भांति प्रशासन, व्यवस्था वित्त और बजट संबंधी विषयों की बाबत शक्तियों का प्रयोग करना;

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण की सम्पत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबंध करना;

(घ) केन्द्रीय प्राधिकरण के खातों को, जिसके अंतर्गत उनकी बाबत आवधिक जांच और लेखा परीक्षा भी है, सही और उचित ढंग से रखना;

(ङ) केन्द्रीय प्राधिकरण की वार्षिक आय और व्यय का लेखा और तुलना पत्र तैयार करना;

(च) सामाजिक कार्यकर्ता समूहों और राज्य विधित सहायता प्राधिकरणों से संपर्क बनाए रखना;

(छ) अद्यतन और पूर्ण सांख्यिकीय जानकारी रखना, जिसके अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति भी है ;

(ज) परियोजना प्रस्तावों पर वितीय सहायता के लिए कार्रवाई करना और उनके उपयोग किए जाने का प्रमाण पत्र जारी करना,

(झ) विधिक सेवा कार्यक्रम के संबंध में समाएं/ गाइडेंस और कार्यजाताएं आयोजित करना और उनकी रिपोर्ट तैयार करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(ञ) आम जनता को विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए वीडियो/ वृत्त चित्र बनाना, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशनों को प्रस्तुत करना; और

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो केन्द्रीय प्राधिकरण के दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए समीचीन हो ।

केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य और सदस्य सचिव की पदावधि और उससे संबंधित अन्य शर्तें :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य एक बार से अनधिक की अवधि के लिए पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने का पात्र होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य को, यदि केन्द्रीय सरकार, की राय में, उसका सदस्य बना रहना वांछनीय नहीं है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

(3) यदि नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य त्यागपत्र या मृत्यु, जैसे किसी कारण से केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहा जाता है तो, रिक्त पद उसी रीति में, जैसा कि मूल नामनिर्देशन के लिए अपनाई जाती है, भर लिया जाएगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उस सदस्य की जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया है, शेष अवधि के लिए, सदस्य रह सकेगा।

(4) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सभी सदस्य केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं की बाबत, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्तों के संदाय के लिए हकदार होंगे और उसका, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित श्रेणी "क" के अधिकारियों को लागू नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा।

(5) यदि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो, वह यथास्थिति या तो अपने मूल विभाग से या केन्द्रीय प्राधिकरण से केवल एक बार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

(6) सदस्य सचिव, 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(7) सदस्य सचिव के वेतन और भत्ते, फायदे और हकदारी, जैसे सभी मामले केन्द्रीय सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू नियमों से शासित होंगे।

(8) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जो, यथास्थिति राज्य न्यायिक उच्चतर सेवा या केन्द्रीय/राज्य की अन्य संगठित सेवा का है, उसकी सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति हो जाती है तो, वह जहां तक उसका संबंध अनुशासनिक मामलों से है, अपने मूल संवर्ग की सेवा शर्तों द्वारा शासित होगा।

(9) सदस्य सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर हो सकेगी।

8. केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या :—केन्द्रीय प्राधिकरण के पास, सचिवालयिक सहायता और अपने दिन प्रतिदिन के कृत्यों को करने के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी होंगे जितने इन नियमों की अनुसूची में उपबंधित है या जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

9. धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन और भत्ते :—

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी इन नियमों को अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपबंधित या केन्द्रीय सरकार के समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन और भत्ते, फायदे और हकदारी तथा अनुशासनिक विषय जैसे सभी मामलों में केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के नियमों से उसी प्रकार शासित होंगे जैसे वे समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू होते हैं।

(3) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी उन अन्य सुविधाओं और फायदों के हकदार होंगे जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।

10. धारा 3-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं—(1) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :—

- (i) भारत का महा-न्यायवादी,
- (ii) भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय,
- (iii) विधि कार्य विभाग में अपर सचिव या उसके नामनिर्देशिनी; भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में अपर सचिव या उसके नामनिर्देशिनी; और
- (iv) उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार।

(3) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अन्य सदस्यों को उनमें से नामनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके पास इस नियम के उपनियम (4) में विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

(4) कोई व्यक्ति जब तक सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह—

- (क) विधि के क्षेत्र में कोई प्रख्यात व्यक्ति न हो;
- (ख) ऐसा कोई व्यक्ति प्राप्त व्यक्ति जो विधि सेवा स्कीम के कार्यान्वयन में विशेष रुचि रखता हो, या
- (ग) कोई ऐसा विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जो कमजोर वर्गों जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्रियाँ, बालक, ग्रामीण और शहरी श्रमिक भी हैं के उत्थान में न लगा हो।

11. धारा 3क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के लिए अनुभव और अर्हताएँ—कोई व्यक्ति सचिव के रूप में नियुक्त के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

- (1) उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री का संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न पंक्ति का कोई अधिकारी न हो, या
- (2) केन्द्रीय सरकार के निदेशक के पद की पंक्ति का कोई अधिकारी, जो विधि में डिग्री न रखता हो।

12. यदि मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष है, तो उस व्यक्ति को अधिकतम वार्षिक आय की सीमा जो उसे धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार बनाती है—भारत का कोई ऐसा नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय 18,000 हजार रु. (अठारह हजार रुपए) से अधिक नहीं है वह इस अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा।

13. धारा 19 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों के अनुभव और अर्हताएँ—ऐसा कोई व्यक्ति लोक अदालत में सम्मिलित किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

- (क) विधिक व्यक्ति क. सदस्य न हो, या
- (ख) ऐसा व्यक्ति प्राप्त व्यक्ति जो विधिक सेवा स्कीम और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विशेष रुचि न रखता हो, या
- (ग) कोई ऐसा विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जो कमजोर वर्गों जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्रियाँ, बालक, ग्रामीण और शहरी व्यक्ति भी हैं, के उत्थान में न लगा हो

अनुसूची

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में कर्मचारियों की प्रस्तावित संख्या

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की सं.
I. अधिकारी			
1.	सदस्य सचिव	7300-7600 रु.	1
2.	उप सचिव	3700-5000 रु.	2
3.	निजी सचिव	3000-4500 रु.	3
4.	अनुभाग अधिकारी	2000-3500 रु.	4
योग :			10
II. स्थापना			
1.	लेखाकार	1640-2900 रुपए	1
2.	सहायक	1640-2900 रु.	2
3.	आशुलिपिक ग्रेड "सी"	1640-2900 रु.	3
4.	समाज विज्ञान अनुसंधान सहायक	1400-2600 रु.	1
5.	मुद्रण सहायक	1400-2600 रु.	1
6.	पुस्तकाध्यक्ष	1200-2040 रु.	1
7.	आशुलिपिक टंकक	1200-2040 रु.	4
8.	रोकड़िया	1200-2040 रु.*	1* विशेष वेतन सहित
9.	अवर श्रेणी लिपिक	950-1500 रु.	8
10.	स्टाफ काग शिप	950-1500 रु.	4
11.	जमादार	775-1025 रु.	3
12.	दफ्तरी	775-1025 रु.	2
13.	गैस्टेटर/प्लेन पेपर	750-940 रु.*	1
14.	चपरासी	750-940 रु.	6
15.	फराश	750-940 रु.	2
16.	मफाईवाला	750-940 रु.	2
योग :			42
अधिकारियों और कर्मचारियों का कुल योग :			52

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1995

G.S.R. 762(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Legal Services Authority Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987;

(b) "Central Authority" means the National Legal Services Authority constituted under section 3 of the Act;

(c) "Member" means the members of the Central Authority nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Act;

(d) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Central Authority appointed under sub-section (3) of the Act;

(e) all other words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. The number, experience and qualifications of other members of the Central Authority.—(1) The Central Authority shall consist of not more than twelve members.

(2) The following shall be the ex-officio members of the Central Authority, namely:—

(i) Secretary,
Department of Legal Affairs,
Ministry of Law, Justice and
Company Affairs,
Government of India or any of his nominee

(ii) Secretary,
Department of Expenditure,
in the Ministry of Finance,
Government of India or any of his nominee;
and

(iii) two Chairman of the State Legal Services Authorities as may be nominated by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India:

Provided that the Patron-in-Chief of the Central Authority may nominate, until the constitution of State Authorities under the Act, Chairman of any two of the State Legal Aid and Advice Boards or Committees, by whatever name called, existing prior to such constitution.

(3) The Central Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of India, other members from amongst those possessing the experience and qualifications prescribed in sub-rule (4) of this rule.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the Central Authority unless he is—

(a) an eminent person in the field of law; or

(b) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes; or

(c) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, children, rural and urban labour.

4. Appointment of Member-Secretary.—The Central Government shall in consultation with the Chief Justice of India, appoint a person to be the Member-Secretary of the Central Authority, possessing experience and qualifications as prescribed in rule 5.

5. The experience and qualifications of the Member-Secretary of the Central Authority and his powers and functions.—A person shall not be qualified for appointment as Member-Secretary unless he is—

(a) an officer of the Indian Legal Service who has held a post not below the rank of Additional Secretary to the Government of India; or

(b) a member of the State Higher Judicial Service who has held the post of District Judge atleast for three years; or

(c) an officer of other organised Central Services who has held a post of Joint Secretary to the Government of India or equivalent for a minimum period of three years; or

(d) an officer of the organised State Services who has held a post equivalent to the Joint Secretary to the Government of India for a minimum period of five years.

Preference will be given to persons possessing administrative, financial and legal aid experience.

6. Powers and Functions of the Member-Secretary.—The powers and functions of the Member-Secretary, inter alia, shall be—

(a) to work out modalities of the Legal Services Schemes and Programmes approved by the Central Authority and ensure their effective monitoring and implementation throughout the country;

(b) to exercise the powers in respect of administrative, finance and budget matters as that of the Head of the Department in a Central Government;

(c) to manage the properties, records and funds of the Central Authority;

(d) to maintain true and proper accounts of the Central Authority including checking and auditing in respect thereof periodically;

(e) to prepare Annual Income and Expenditure Accounts and Balance Sheet of the Central Authority;

(f) to liaise with the Social Action Groups and the State Legal Services Authorities;

(g) to maintain up-to-date and complete statistical information, including progress made in the implementation of various Legal Services Programmes from time to time;

(h) to process project proposals for financial assistance and issue Utilisation Certificates thereof;

(i) to convene Meetings/Seminars and Workshops connected with Legal Services Programmes and preparation of Reports and follow-up action thereon;

(j) to produce video/documentary films, publicity material, literature and publications to inform general public about the various aspects of the Legal Services Programmes; and

(k) to perform such other functions as may be expedient for efficient functioning of the Central Authority.

7. The terms of office and other conditions relating thereto, of members and Member-Secretary of the Central Authority.—

(1) The members of the Central Authority nominated by the Central Government under sub-rule (3) of rule 3, shall hold office for a term of two years and a retiring member shall be eligible for renomination for not more than one term.

(2) A member of the Central Authority nominated by the Central Government under sub-rule (3) of rule 3 may be removed by the Central Government if in the opinion of the Central Government, it is not desirable to continue him as a member.

(3) If any member nominated under sub-rule (3) of rule 3 ceases to be a member of the Central Authority, for any reason such as resignation or death, the vacancy shall be filled up in the same manner as the original nomination and the person so nominated shall continue to be a member for the remaining term of the member in whose place he is nominated.

(4) All members nominated under sub-rule (3) of rule 3 shall be entitled to payment of travelling allowance and daily allowance in respect of journeys performed in connection with the work of the Central Authority and shall be paid by the Central Authority in accordance with the rules as are applicable to Grade 'A' officers, as amended from time to time.

(5) If a nominated member is a government employee, he shall be entitled to only one set of travelling allowance and daily allowance either from his parent department, or, as the case may be, from the Central Authority.

(6) The Member-Secretary shall hold office for a term not exceeding five years or till the age of 62 years, whichever is earlier.

(7) In all matters like pay, allowances, benefits and entitlements, the Member-Secretary shall be governed by rules as are applicable to the persons holding equivalent posts in the Central Government.

(8) If an officer of the State Higher Judicial Service or, as the case may be, of other organised Central/State Services, is appointed as Member-Secretary he shall be governed by the service conditions of his parent cadre, in so far as disciplinary matters are concerned.

(9) The appointment of the Member-Secretary may be on deputation basis.

8. The number of officers and other employees of the Central Authority. The Central Authority shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in Schedule to these rules or as may be notified by the Central Government from time to time.

9. The conditions of service and the salary and allowances of officers and other employees of the Central Authority under sub-section (6) of Section 3.—(1) The officers and other employees of the Central Authority shall be entitled to draw pay and allowances in the scale of pay indicated against each post in the Schedule to these rules or at par with the Central Government employees holding equivalent posts.

(2) In all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the Central Authority shall be governed by the Central Government as are applicable to persons holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the Central Authority shall be entitled to such other facilities and benefits as may be notified by the Central Government from time to time.

10. The number, experience and qualifications of members of the Supreme Court Legal Services Committee under clause (b) of sub-section (2) of section 3A.—(1) The Supreme Court Legal Services Committee shall consist of not more than nine members.

(2) The following shall be the ex-officio members of the Supreme Court Legal Services Committee :—

- (i) Attorney General of India;
- (ii) Additional Secretary in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Government of India or his nominee;
- (iii) Additional Secretary in the Department of Expenditure of the Ministry of Finance, Government of India or his nominee; and
- (iv) Registrar General of the Supreme Court of India.

(3) The Central Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of India, other members from amongst these possessing the qualification and experience prescribed in sub-rule (4) of this rule.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member unless he is—

- (a) an eminent person in the field of law; or
- (b) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes; or
- (c) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, children rural and urban labour.

11. The experience and qualifications of Secretary of the Supreme Court Legal Services Committee under clause (b) of

sub-section (2) of section 3A.—A person shall not be qualified for appointment as Secretary unless he is—

- (a) an officer of the Supreme Court Registry not below the rank of Joint Registrar; or
- (ii) officers of the rank of Director from the Central Government, possessing a degree of Law.

12. The upper limit of annual income of a person entitling him to legal services under clause (h) of section 12, if the case is before the Supreme Court.—Any citizen of India whose annual income from all sources does not exceed Rs. 18,000 (Rupees eighteen thousand) shall be entitled to legal services under clause (h) of section 12 of the Act.

13. The experience and qualifications of other persons of the Lok Adalats organised by the Supreme Court Legal Services Committee specified in sub-section (3) of section 19.—A person shall not be qualified to be included in the Lok Adalat unless he is—

- (a) a member of the legal profession; or
- (b) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes; or
- (c) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, children, rural and urban labour.

[F. No. 6(22)/95-NAISA]

Dr. V. K. AGARWAL, Addl. Secy.

SCHEDULE

PROPOSED STRENGTH OF THE STAFF OF THE NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY CONSEQUENT UPON THE ENFORCEMENT OF THE LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT

S. No.	Designation	Scale of pay	No. of posts
I. OFFICERS			
1.	Member Secretary	Rs. 7300 - 7600	1
2.	Deputy Secretary	Rs. 3700—5000	2
3.	Private Secretary	Rs. 3000 - 4500	3
4.	Section Officer	Rs. 2000 - 3500	4
	Total:		10
II. ESTABLISHMENT			
1.	Accountant	Rs. 1640—2900	1
2.	Assistant	Rs. 1640 - 2900	2
3.	Steno Gr. 'C'	Rs. 1640—2900	3
4.	Social Science Res. Asstt.	Rs. 1400 - 2600	1
5.	Printing Assistant	Rs. 1400 - 2600	1
6.	Librarian	Rs. 1200—2040	1
7.	Steno Typist	Rs. 1200—2040	4
8.	Cashier	Rs. 1200—2040*	1
9.	Lower Division Clerk	Rs. 950—1500	8
10.	Staff Car Driver	Rs. 950—1500	4
11.	Jamadar	Rs. 775 - 1025	3
12.	Daftry	Rs. 775—1025	2
13.	Gestetner/Plain Paper Copier Operator	Rs. 750 - 940*	1
14.	Peon	Rs. 750 - 940	6
15.	Farash	Rs. 750—940	2
16.	Safaiwala	Rs. 750—940	2
	Total:		42
	GRAND TOTAL OF OFFICERS AND STAFF		52